



'बजट में दिल्ली और बिहार के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई है'

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम् ने कहा, केन्द्रीय बजट का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना है

- चिदम्बरम् ने आरोप लगाया, बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, समाज कल्याण, कृषि क्षेत्र के बजट आठांठन में कटौती की गई है।
- चिदम्बरम् ने अनुसूचित जाति, जनजाति, ओडीसी तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के बजट में कटौती को कूर कदम बताया।
- उहोंने कहा, नई टैक्स प्रणाली में मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, खासकर, उहोंने जो हर माह 60,000 से एक लाख रुपए तक कमाते हैं, लैकिन पैट्रोल, डीजल में जीएसटी में कोई कटौती नहीं की गई है।
- उहोंने कहा, बेरोजगारी दूर करना सबसे अहम मांग है, पर, रोजगार सूजन की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

मदद मिल सकें बेरोजगारी दूर करने पर भी कुछ नहीं किया गया है जो कि गया है जहां अगले वर्ष आम चुनाव होने वाले हैं।

बजट का मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना है ना कि देश की जनता के जीवन की सुधारना। चिदम्बरम् ने कहा अपना आठांठ बजट पेश करते हुए वित्त भारत-आमनिर्भय भजनलाल के संकल्प को मजबूती देता साथ ही, बजट में मेक इन इंडिया से अब 'मेक फॉर बल्टी' की अवधारणा के साथ देश को वैश्वक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा दी गई है।

उहोंने कहा कि जनता का यह बजट भारत के जन-जन के भविष्य को निखारेगा तथा बजट से समृद्ध और सशक्त राजस्थान के विजन को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में राजस्थान के प्रस्तावों को मजबूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।

बद्धने, पावर सेक्टर रिफर्म के लिए विशेष सहायता देने एवं राज्य को गूंजांग विवेश के लिए व्याज मुक्त प्रदान किये जाने के संबंध में अल्पसंख्यकों के लिए निश्चारित बजट से भी कटौती की गई है जो कूर कदम है।

बज बजट को रेटिंग देने के बारे में पृष्ठ गया तो एक पवर वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली व बिहार के मतदाता इसे हार्द रेटिंग देंगे पर शेष भारत के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती।

नाबालिंग से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास

जयपुर, 1 फरवरी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिंग कांजिंज छात्रों के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रोहित शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके हालत में 24 वर्षीय अभियुक्त ने 2.55 लाख रुपए का जुमाना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त

- पॉक्सो कोर्ट ने 24 वर्षीय आरोपी युवक रोहित शर्मा पर 1.35 लाख रुपए का जुमाना भी लगाया।

ने नाबालिंग पीड़ितों को जन्मदिन की पार्टी में ले जाने का बहाना बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा जीड़ीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- रेल्वे को गत वर्ष 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।

- रेल्वे के आधुनिकीकरण की बड़ी-बड़ी घोषणाओं को देखते हुए इस वर्ष उम्मीद थी कि सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का 25 प्रतिशत रेल्वे को देगी, पर ऐसा नहीं हुआ।

- रेल्वे को 31,000 किलोमीटर रेल्वे ट्रैक का विद्युतीकरण करना है और रेल दुर्घटना नियोगित तंत्र 'कवच' भी स्थापित करना है, साथ ही मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहन देना है। यह सब बजट प्रस्तावों में परिलक्षित नहीं हो रहा है।

कॉर्डोस के निर्माण की योजनाओं या आँकड़े के स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में इसे देने के निर्माण के बारे में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की अवश्यकता पर चुप्पी साध रखी है। जरूरत है। इसलिये, सीतारमण के बजट शुरुकार को पेश किये गये प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। 'इकोनॉमिक सर्वे' में, सरकार ने भारतीय रेलवे, जिसे हाल ही के बारे में आधुनिकीकरण, जैसे डेलिकेट फ्रेट

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हार्ड स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त बजट में यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में यह घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जुमाना को 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जेर नये र

